विचार बिन्दु

उत्साह से बढ़कर कोई दूसरा बल नहीं है, उत्साही मनुष्य के लिए संसार में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। –वाल्मीकि

भारत अपना ग्लोबल जीपीएस सिस्टम बनाने की राह पर

स्मार्टफोन मैप से लेकर सटीक हथियारों तक, सैटेलाइट नेविगेशन आज, जिंदगी और युद्ध दोनों का अनिवार्य हिस्सा बन चुका है। जिस किसी ने अपने स्मार्टफोन मैप का कभी इस्तेमाल किया है या फिर ओला या ऊबर टैक्सी बुक की है तो इसका मतलब है उसने जीपीएस याने सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया है। बहुत लोग नहीं जानते कि जीपीएस, यानी ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, अमेरिका का एक विराट नेटवर्कहै। अमरीका के जीपीएस, जिसे ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम कहते हैं, जैसे और भी सिस्टम अभी दुनिया में उपलब्ध हैं, मगर इस व्यवस्था में अमरीका का ही बोल–बाला है। अब भारत भी अपना झूड़ का जीपीएस सिस्टम विकसित कर रहा है। यह सिस्टम सैटेलाइटों के समूह के साथ काम करते हैं। इस वक़्त चार वैश्विक सैटेलाइट सिस्टम पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे हैं। ये हवाई जहाज, नाविक जहाज, सड़क के वाहनों, और यहां तक कि होटल खोज रहे पर्यटकों को तथा शहरों में टैक्सी चालकों को भी रास्ता दिखाते हैं। साथ ही ये युद्ध में भी अहम भूमिका निभाते हैंऔर एक दूसरे पर सटीक वार करते हैं। सैटेलाइट नेविगेशन वास्तव में समय का खेल है। यह वैश्विक सैटेलाइट सिस्टम बहुत सटीक परमाणु घड़ियां होती हैं। पृथ्वी के चक्कर लगा रहे सैटेलाइट्स हर पल, अपनी बिल्कुल सटीक स्थिति और सिग्नल भेजने के सही समय को ब्रॉडकास्ट करते रहते हैं। धरती पर इस्तेमाल होने वाले जीपीएस जैसे डिवाइस, इन सिग्नलों को पकड़ कर अपनी सही लोकेशन पहचान पाते हैं। वैश्विक सैटेलाइट सिस्टम चार सैटेलाइटों के सिग्नल से अक्षांश, देशांतर और ऊंचाई का डेटा निरंतर लेता रहता है। इस दौरान किसी भी सैटेलाइट के जरा से समयान्तर को भी वह दुरुस्त करता रहता है। यह तकनीक बहुत तेज और सटीक है। लेकिन इसमें एक कमजोरी भी छिपी है। विशेषज्ञ बताते हैं कि ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के सिग्नल काफी नाजुक होते हैं। ये सिग्नल इतने कमजोर होते हैं कि इनके पास अगर रेडियो तरंगों में, चाहे गलती से या जानबूझकर कुछ शोर आ जाये, तो इनके रिसेप्शन में दखल आ सकता है। चुनौती यह है कि इसे समझा जाय और जोखिम कम करने के लिए कदम उठाये जाय और यह सिस्टम हमें सुविधाएं डेटा रहे।

दुनिया में इस समय चार वैश्विक नेविगेशन शक्तियां हैं वे हैं अमेरिका, रूस, यूरोप और चीन। सबसे पहले 1970 के दशक में दो ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम अमेरिका और सोवियत यूनियन ने विकसित किए थे। अमेरिका ने 'जीपीएस' बनाया, जो पूरी दुनिया के क्षेत्र को कवर करने वाला पहला सैटेलाइट नेविगेशन नेटवर्क बना। आज सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला सिस्टम भी यही है। लगभग उसी समय सोवियत रूस ने अपना 'ग्लोनास' सिस्टम बनाया। उसके बाद 2000 के दशक की शुरुआत में यूरोपीय संघ ने यह सोचकर कि जीपीएस पर निर्भर रहना यूरोप को अमेरिका की रणनीतिक तकनीक पर निर्भर बना देगा, तो उन्होंनेअलग से अपना 'गैलिलियो' सिस्टम बनाना शुरू किया। चीन का 'बाइडू' सिस्टम इन चारों में सबसे नया है। यूरोप की तरह, चीन भी अमेरिका के जीपीएस पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता था। ये चारों सिस्टम लगभग एक जैसे हैं, और नागरिक और सैन्य दोनों कामों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। 'जीपीएस', 'ग्लोनास' और 'गैलिलियो' लगभग एक जैसी कक्षाओं पर लगभग 19,000 से 23,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर समान संख्या में सैटेलाइट इस्तेमाल करते हैं। 'बाइडू' अपने सिस्टम में ऊंची कक्षाओं वाली सैटेलाइट्स जोड़ता है जिससे उसे एशिया में स्थानीय कवरेज बेहतर मिले। इनमें से हर–एक सिस्टम धरती पर किसी भी जगह संकेत भेज सकता है, चाहे वह कलाई की घड़ी जितनी छोटी डिवाइस ही क्यों न हो।

ज्यादातर डिवाइस कई तरह की सैटेलाइट समूहों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यह डिवाइस पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए किसी की स्मार्टवॉच 'जीपीएस' और 'ग्लोनास' दोनों का इस्तेमाल कर सकती है। जापान औरभारत के पास भी ऐसे सिस्टम हैं, लेकिन वे पूरी दुनिया के क्षेत्र को कवर नहीं करते हैं। वे सीमित नेविगेशन देते हैं। जापान का नेविगेशन सिस्टम है 'क्यूजेडएसएस' जो एशिया ओशेनिया क्षेत्र में काम करता है, हालांकि इसका मुख्य फोकस जापान पर ही है। भारत का अपना नेविगेशन सिस्टम 'नाविक' है। 'नाविक' यानी नेविगेशन विद इंडियन कॉनस्टेलेशन। यह एक स्वतंत्र नेविगेशन सिस्टम है जिसे भारतीय अंतरिक्ष शोध संस्थान यानी इसरो ने विकसित किया है। नाविक को 2006 में मंजूरी दी गई थी और इसका बजट था 17.4 करोड़ डॉलररखा गया था। इसे 2011 में तैयार होना था लेकिन 2018 में जाकर इसने काम करना शुरू किया। 'नाविक' में 8 उपठाह जुड़े हुए हैं जो 1500 किलोमीटर ऊपर से भारत की पूरी जमीन पर नज़र रखते हैं। फिलहाल 'नाविक' का सीमित इस्तेमाल हो रहा है। इसे सार्वजनिक गाड़ियों पर निगाह रखने, गहरे समंदर की तरफ जाने वाले मछुआरों को सावधान करने और प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति पर नज़र रखनेतथा जानकारी देने के लिये इस्तेमाल किया जाता है। ट्रेनों की ट्रैकिंग के लिए भी इसका इस्तेमालकिया जाता है। भारतीय वैज्ञानिक अब इसे इसे स्मार्टफोन में इस्तेमाल के लिए तैयार कर रहे हैं। दूसरे नेविगेशन सिस्टमों और 'नाविक' में मुख्य फर्क इलाके की निगरानी काहै। दूसरी जीपीएस सेवाएं दुनिया के सारे देशों में काम करती हैं और उनके उपठाह दिन भर में धरती का दो बार चक्कर लगाते हैं। इसके उलट 'नाविक'फिलहाल केवल भारत और उसके आसपास के इलाके पर नज़र रखता है।

सैटेलाइट नेविगेशन वास्तव में समय का खेल है। यह वैश्विक सैटेलाइट सिस्टम बहुत सटीक परमाणु घड़ियां होती हैं। पृथ्वी के चक्कर लगा रहे सैटेलाइट्स हर पल, अपनी बिल्कुल सटीक स्थिति और सिग्नल भेजने के सही समय को ब्रॉडकास्ट करते रहते हैं। धरती पर इस्तेमाल होने वाले जीपीएस जैसे डिवाइस, इन सिग्नलों को पकड़ कर अपनी सही लोकेशन पहचान पाते हैं। वैश्विक सैटेलाइट सिस्टम चार सैटेलाइटों के सिग्नल से अक्षांश, देशांतर और ऊंचाई का डेटा निरंतर लेता रहता है। इस दौरान किसी भी सैटेलाइट के जरा से समयान्तर को भी वह दुरुस्त करता रहता है। यह तकनीक बहुत तेज और सटीक है। लेकिन इसमें एक कमजोरी भी छिपी है। विशेषज्ञ बताते हैं कि ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के सिग्नल काफी नाजुक होते हैं। ये सिग्नल इतने कमजोर होते हैं कि इनके पास अगर रेडियो तरंगों में, चाहे गलती से या जानबूझकर कुछ शोर आ जाये, तो इनके रिसेप्शन में दखल आ सकता है

भारत ने 2021 में सेटेलाइट नेविगेश नीति का जो प्रस्ताव तैयार किया था उसमें कहा गया है कि सरकार नेविगेशन सिस्टम के कवरेज को विस्तार देने पर काम करेगी जिससे कि इसे क्षेत्रीय से वैश्विक बनाया जा सके। इसके पीछे 'नाविक' के सिग्नल को दुनिया भर में मुहैया कराने का लक्ष्यरखा गया है। पिछले साल अगस्त में भारत सरकार ने कहा कि 'नाविक', ''सटीक स्थिति (पोजिशन एक्यूरेसी) बताने के मामले में अमेरिका के जीपीएस सिस्टम जितना ही अच्छा बन गयाहै।'' सरकार का कहना है कि 'नाविक' को विदेशी उपठाहों और नेविगेशन सर्विस की जरूरतों पर निर्भरता से मुक्त करने किये बनाया गया है। खासतौर से ''रणनीतिक क्षेत्रों'' में।'जीपीएस' और 'ग्लोनास' जैसे सिस्टम पर हमेशा भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि ये अपने देशों की सुरक्षा एजेंसियों के हाथों ऑपरेट किये जाते हैं। ऐसे में यह मुमकिन है कि नागरिक सेवाओं को दोयम दर्जे में रखा जाये या फिर कभी सेवा से वंचित कर दिया जाये। केंद्र सरकार का कहना है, ''नाविक एक घरेलू सिस्टम है जो भारत के नियंत्रण में है। इसमें किसी खास स्थिति में यह सेवा नहीं देने या फिर वापस लेने का जोखिम नहीं है। भारत अपने मंत्रालयों को भी 'नाविक' के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित कर रहा है। सरकार 5जी मोबाइल सैटों में नाविक अनिवार्य करने की योजना बना रही है। साथ ही अलग– अलग उद्योगों में इसके इस्तेमाल में आने वाली समस्याओं के समाधान कीभी कोशिश हो रही है।

दुनिया भर की सेनाएं भी अब सामग्री प्रबंधन, नक्शे बनाने और सैन्य कार्रवाई की योजना तैयार करने के लिए सैटेलाइट नेविगेशन पर निर्भर हैं। इनकी मदद से क्रूज मिसाइल और तथाकथित 'स्मार्ट बम जैसे हथियारों को गाइड किया जा सकता हैं। ड्रोन चलाने के लिए भी इन्हें इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसी दोहरे इस्तेमाल के कारण सैटेलाइट खुद एक निशाना बन जाते हैं। यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस और यूक्रेन ने सिग्नल ''जैमिंग'' जैसी इलेक्ट्रॉनिक युद्ध तकनीकें इस्तेमाल कीं। जैमिंग का मतलब है सिग्नल में दखल डालकर उसे बिगाड़ देना, और ''स्पूफिंग'' का मतलब है जमीन पर जीपीएस आधारित सिस्टम को धोखा देना। स्पूफिंग करना जैमिंग से कठिन है, लेकिन इससे दुश्मन को गुमराह किया जा सकता है।नेविगेशन सिस्टम यह भी दिखा सकता है कि कोई यान 400 नॉट्स की स्पीड से दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ रहा है, जबकि असल में वह बाड़मेर के बाहर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कार चला रहा होता हैं। इस तरह यह तकनीक किसी क्षेत्र से गुजर रहे जहाजी बेड़े को अपनी लोकेशन छिपाने मेंभी मदद कर सकती है।वर्तमान में अमरीका ईरान युद्ध में इस तकनीक का उपयोग होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरते जहाजों में अत्यंत बारीक त्रुटियां डालने के लिए भी किया गया है, जिससे वह जहाज गलती से किसी और देश के जलक्षेत्र में घुस जाए, और वह देश उसे रोक कर अवैध घुसपैठ के आरोप में उस पर कब्जा कर ले। अमेरिका की रेसिलिएंट नेविगेशन एंड टाइमिंग फाउंडेशन के अध्यक्ष का कहना है कि यह समस्या यूरोप और अमेरिका के लिए रूस और चीन से भी बड़ी है, क्योंकि रूस और चीन के पास ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के साथ ही अपने घरेलू बैकअप सिस्टम भी हैं। पश्चिम के पास ये नहीं हैं। एक अन्य विशेषज्ञ का मानना है कि सबसे परेशान करने वाली बात यह है कि ऐसी कोई तकनीक मौजूद नहीं है जो ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम संबंधी दिक्कतों को पूरी तरह हल कर दे।

ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के विकल्प बनाने की भी कोशिशें हुई हैं, लेकिन अभी युद्ध में, सबसे कारगर और तेज उपाय, जैमर से उसे नष्ट कर देना ही है।ऐसे में भारत का अपना नेविगेशन सिस्टम 'नाविक' बनाना और उसे आगे विकसित करना महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत ने बड़ी प्रगति की है, लेकिन अभी यह विकास के चरण में है।आनेवालेवर्षोंमेंभारतीय सैटेलाइट सही समय पर लॉन्च हो जाते हैं, तो'नाविक' जीपीएस का एक मजबूत विकल्प बन सकता है।

अतिथि संपादक,
राजेन्द्र बोड़ा,
(वरिष्ठ पत्रकार एवं विश्लेषक)

धन संग्रह गाय के नाम - खर्च के लिए दूसरे काम

गौवंश का 'गौधन से निराश्रित पशु' होना विचार के लिए सामयिक एवं प्रासंगिक विषय बन गया है

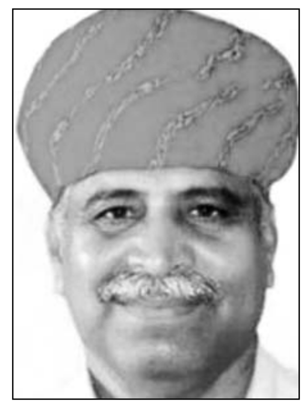

रामपाल जाट

देश के पशुपालन मंत्री राजीव रंजन के अनुसार वर्ष 2023–24 में गायों की संख्या 19.30 करोड़ थी। देश में सरकार द्वारा संचालित एवं पंजीकृत गौशालाओं की संख्या 7,676 है, जिनमें गायों की संख्या लगभग 14 लाख है। विश्व की सबसे बड़ी गौशाला पथमेड़ा है। उसके द्वारा संचालित 15 गौशालाओं में गायों की संख्या लगभग 1,55,000 है। विश्व में सर्वाधिक गायों की संख्या भी भारत में है। वर्तमान में सात व्यक्तियों के लिए एक गाय हैं जबकि वर्ष 1947 में एक व्यक्ति के लिए औसत चार गाय थी, वर्तमान में सात व्यक्तियों के लिए एक गाय है। महाभारत काल में तो गायों के लिए युद्धों का उल्लेख गौ धन के महत्व को दर्शाता है। जो गाय घर–परिवार एवं खूंटे की शोभा एवं सम्मान थी, वे ही गायें सड़कों पर हैं तथा निराश्रित पशु के रूप में चिन्हित हो रही हैं। उनसे फसलों की रक्षा के लिए गोपालक किसानों द्वारा ही शासकों से विनती की जाती है। गौ वंश का 'गौधन से निराश्रित पशु' होना विचार के लिए सामयिक एवं प्रासंगिक विषय बन गया है।

भारत में दुधारू गायों में गुजरात की गिर, पंजाब एवं उत्तर प्रदेश की साहीवाल, पाकिस्तान के आसपास क्षेत्र से लालसिंधी, राजस्थान एवं गुजरात की थारपारकर एवं काकरेज, राजस्थान के शुष्क प्रदेशों की राठी, आंध्र प्रदेश की ओगोल, महाराष्ट्र की देवनी, केरल की वेचुर नस्ल की गायें प्रमुख है। भारतीय कृषि में बैल सबसे बड़ा ऊर्जा का स्त्रोत रहा है। इसी कारण गाय जब भी बछड़ा देती थी तो परिवार में दीपावली जैसा उत्सव अनुभव किया जाता था, बछडी देने पर दीपावली जैसी प्रसन्नता परिवार में दिखाई नहीं देती थी। दूसरी ओर भारतीय कृषि में परस्पर पूरकता विद्यमान थी।

खेती से बचने वाला चारा, गोवंश के लिए उपयोग में आता था और गौवंश से बचने वाला गोबर एवं मूत्र खेत का उपजाऊपन बढ़ाने के लिए खाद के रूप में काम आता था। इस प्रणाली में परस्परावलंबिता भी थी। कृषि के मशीनीकरण एवं रासायनिकरण से जो चारा खेती से बचता है, वह जलाया जाता है, उससे वायु प्रदूषित होती है, जो गौवंश से बचता है, वह गोबर एवं मूत्र ट्रेक्टर में उपयोग नहीं हो पाता है। इसे ईख यानि गन्ने से समझा जा सकता है। इसके तीन भाग होते हैं, जिसमें निचला जड़ भाग बीज के रूप में, मध्य भाग तना रस के रूप में एवं ऊपरी भाग पत्तियां चारे के रूप में उपयोग में आती है। प्रकृति की यह अद्भुत देन भारत की वैज्ञानिक कृषि प्रणाली को सहज रूप से समझा देती है।

अन्न से शरीर को शारीरिक एवं मानसिक बल प्राप्त होता है, इसलिए उसे देवस्वरूप माना गया है। अन्न का आशय अमृतान्न है। खेती के रासायनिकरण से यह विषान्न बन गया। जो शरीर को पौष्टिकता देने के स्थान पर रोग एवं विभिन्न प्रकार की कैंसर जैसी असाध्य बीमारियां दे रहा है। आयु में वृद्धि के स्थान पर अल्पायु में हृदयाघात की घटनाएं बढ़ रही है। सरकार जेनेटीकली मॉडिफाइड नपुंसक बीजों को प्रोत्साहित कर खेती का खर्च बढ़ाकर किसानों को अपनी जीवन लीला समयपूर्व समाप्त करने की ओर धकेल रही है। रासायनिकरण एवं मशीनीकरण से खेती का खर्चा बढ़ रहा है, इससे ट्रैक्टर जैसे कृषि यंत्र, उपकरण, खाद, बीज, एवं कीटनाशी बनाने वाली कंपनियां तो मालामाल हो रही हैं किंतु किसान कंगाल हो रहा है।

कंपनियां अपने उत्पादों का लागत से कई गुना दाम वसूल करती हैं और किसानों को उनके उत्पादों का अनेकों बार लागत खर्च भी प्राप्त नहीं हो पाता है। किसान विवश और बेचारा बन गया। कृषि में प्रयुक्त होने वाले सामान एवं सामठी खरीदने जाता है तो सुनना पड़ता है कि 'इस निर्धारित मूल्य पर लेना हो तो लेओ वरना हटो यहां से', वही किसान अपना उत्पाद लेकर बाजार में बेचने जाता है तो उसे सुनना पड़ता है 'इस दाम पर देना हो तो दो वरना हटो यहां से', यानि किसान बेचते एवं खरीदते समय बेचारा बना हुआ है, वह स्वयं को असहाय एवं विवश अनुभव करता है। दुष्परिणामत: किसान ऋणचक्र में फंसता जा रहा है। जो एक दाने से हजार दाने तक पैदा करता है, उसे तो ऋण मुक्त होना चाहिए, तब भी कृषि प्रधान भारत में किसान ऋण की पीड़ा भोग रहा है। गौ आधारित खेती में यह स्थिति संभव नहीं है क्योंकि किसान बाजारवाद की चपेट से बचा रहता है। उसका स्वास्थ्य अच्छा रहने से वह निरोगी होता है, चिकित्सा के लिए चक्कर लगाने नहीं पड़ते हैं एवं औषधियों का खर्चा वहन नहीं करना पड़ता है। उर्वरक एवं मशीनों पर होने वाले खर्च की लूट से भी किसानों को मुक्ति मिलती है, अर्थात श्रेष्ठ समाधान गौ आधारित खेती है। इस हेतु से गौवंश की रक्षा सर्वोपरि है। गौशालाओं की गौवंश की नस्ल बचाने में तो महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके लिए सरकार ने भी सही दिशा में विचार किया और गौशालाओं के संचालन के लिए 2015–16 में 10 उपकर लगाया गया, जिसे गोवंश पर ही खर्च करने का प्रावधान किया। वर्ष 2020–21 के बाद उपकर की मात्रा बढ़कर 30 तक कर दी गयी।

2015–16 से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक प्राप्ति में से खर्च की गई राशि के संबंध में सूचना के अधिकार के अनुसार 2060 करोड़ रुपए शेष है। एक ओर तो निराश्रित गायों के लिए छाया का प्रबंध नहीं होने से वे सड़कों पर है, दूसरी ओर इतनी बड़ी राशि का उपयोग नहीं किया जा रहा है। संभावना यह भी व्यक्त की जा रही है कि गायों के नाम पर उपकर से वसूली जा रही राशि अन्य कार्यों के लिए खर्च की जा रही है। इससे सरकार की गाय के लिए गंभीरता पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है।

कृषि प्रधान भारत की जनता गौ पूजा एवं सेवा को श्रेष्ठ धर्म मानती है। इसीलिए सामान्यतया घरों में बनने वाली पहली रोटी गाय के लिए ही रखे जाने की जाने की श्रेष्ठ परंपरा प्रचलन में रही है। इसी दिशा में गौशालाओं के साथ गौपालकों को भी प्रोत्साहन दिया जाए तो श्रेयस्कर सिद्ध हो सकता है। इस हेतु से उपकर की राशि के खर्चे पर विचार किया जाना भी सार्थक हो सकता है। यह समीकरण भी विचार के लिए समीचीन है कि 5 लाख का शहर 500 गायों की पालना नहीं कर सकता जबकि 500 घरों का गांव 500 गायों को सरलता से रख सकता है। गोवंश की वृद्धि एवं रक्षा के लिए बैल आधारित खेती को सर्वोत्तम उपाय के रूप में अपनाना श्रेष्ठ विचार है। जन–जन की आत्मीय भावनाओं का आधार गौवंश देश के अन्नदाताओं को बाजारवाद एवं ऋणचक्र से मुक्ति दिलाने में कारगर हो सकता है। इस दिशा में सरकार द्वारा आरंभ बैल आधारित खेती के प्रोत्साहन के लिए नकद अनुदान जैसी योजनाओं की निरंतरता अपरिहार्य है।

रामपाल जाट,
राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान महापंचायत।

भारत : अस्थिर दुनिया में आत्मनिर्भरता जरूरी

प्रो. महेश चंद गुप्ता

दुनिया अब अलग–अलग बिखरे देशों का नक्शा मात्र नहीं रही है। यह एक ऐसा तंत्र बन गई है, जिसमें कहीं भी हलचल होती है तो उसकी तरंगें दुनिया के हर कोने तक पहुंचती हैं। हाल में ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच टकराव की स्थिति के बाद पैदा हुए तनाव ने इस सच्चाई को फिर से उजागर कर दिया है। इससे पहले रूस–यूक्रेन युद्ध से भी यह सबक मिल चुका है कि जंग किसी एक भूभाग तक सीमित नहीं रहती। उसके असर सीमाओं से परे जाते हैं। इस बात को हम लागू होते देख रहे हैं।

भारत इस अमेरिका–इजरायल–ईरान संघर्ष का हिस्सा नहीं है, लेकिन उसका असर हमारे यहां साफ दिखाई दे रहा है। पेट्रोल और एलपीजी की आपूर्ति में अस्थिरता, छोटे उद्योगों का ठप पड़ना, निर्यात पर असर–ये सब संकेत दे रहे हैं कि वैश्विक अस्थिरता का बोझ हम भी ढो रहे हैं। दुनिया इतनी छोटी हो चुकी है कि कई लोग इसकी तुलना एक गांव से भी करते हैं। मानना ही होगा कि यह एक ऐसा साझा घर बन चुकी है, जिसकी एक दीवार पर आग लगे तो दूसरी दीवार पर बैठे लोग भी उसकी आंच महसूस करते हैं। यही वजह है कि ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच बढ़ता तनाव सिर्फ युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं रहा। उसकी छाया हमारे रसोईघर, बाजार और छोटे–छोटे काम–धंधों तक आ पहुंची है।

भारत की नीति स्पष्ट रूप से शांति की है, लेकिन वैश्विक व्यवस्था में उसकी भागीदारी इतनी गहरी है कि किसी भी तनाव के असर से बचना संभव नहीं है। शहरों में ठेले पर चाय बेचने वाला हो या मिठाई की दुकान चलाने वाला हलवाई, हर किसी के काम पर इसका असर साफ दिखाई दे रहा है। गैस सिलेंडर की बुकिंग में देरी अब सिर्फ एक असुविधा नहीं, बल्कि रोजमर्रा की कमाई पर चोट बनती जा रही है। इसका बड़ा कारण मूलभूत जरूरतों के लिए हमारा अन्य देशों पर निर्भर होना है। बड़ा सवाल यह है कि क्या हम अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए इतने अधिक बाहरी स्त्रोतों पर निर्भर हो चुके हैं कि कहीं भी हलचल हो और हमारी जमीन हिलने लगे?

यह सच है कि हमारी जरूरतों का बड़ा हिस्सा आज भी आयात किए गए तेल और गैस से पूरा होता है। खाड़ी क्षेत्र में तनातनी बढ़ते ही सप्लाई चेन पर दबाव पड़ता है और उसका सीधा असर हमारे घरों तक पहुंचता है। यह निर्भरता केवल आर्थिक नहीं है, बल्कि रणनीतिक कमजोरी भी है। लेकिन बात केवल ऊर्जा तक सीमित नहीं है। भारत का औद्योगिक और कृषि ढांचा भी कई मायनों में वैश्विक आपूर्ति पर टिका हुआ है। खाद्य तेल से लेकर उर्वरकों तक, इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर रक्षा उपकरणों तक कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें हम पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं हैं। यह स्थिति तब और चिंताजनक हो जाती है जब वैश्विक संकट लंबा खिंचने लगता है।

तीन दशक पहले सद्दाम हुसैन को काबू करने के लिए मित्र देशों द्वारा इराक पर हमलों से डीजल–पेट्रोल के लिए हमारे देश में लगी लंबी कतारें हमें याद हैं। अब हम कमोबेश वैसी ही स्थिति की आशंका देख रहे हैं। बात केवल आयात की नहीं है, निर्यात भी इस संकट से प्रभावित हो रहा है। बीकानेर का भुजिया, महाराष्ट्र के केले, कपड़ा उद्योग और समुद्री उत्पाद आदि सबका अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचना अब पहले जैसा सहज नहीं रहा। जलगांव से रोजाना दो से तीन हजार टन केला खाड़ी देशों व यूरोप को निर्यात होता है, लेकिन इस युद्ध ने निर्यात को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। केले से भरे सैकड़ों कंटेनर बंदरगाहों पर फंसे हुए हैं। इसी प्रकार बीकानेर से भुजिया का निर्यात भी प्रभावित हुआ है। समुद्री रास्तों में असुरक्षा और लागत बढ़ने से कई व्यापारियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। यह केवल माल की आवाजाही का संकट नहीं है, बल्कि इन उद्योगों से जुड़े लाखों लोगों की रोजी–रोटी का भी सवाल है।

भारत की आत्मनिर्भरता की बहस में सूचना एवं प्रौद्योगिकी का क्षेत्र अक्सर नजरअंदाज हो जाता है, जबकि यह आज की अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों के लिए बेहद अहम है। भारत डिजिटल रूप से तेजी से आगे बढ़ा है, लेकिन इस डिजिटल ढांचे की बुनियाद अब भी काफी हद तक विदेशी तकनीक पर टिकी है। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, क्लाउड सेवाएं, सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र बाहरी कंपनियों के नियंत्रण में हैं। ऐसे में वैश्विक तनाव या प्रतिबंधों की स्थिति में यह निर्भरता गंभीर जोखिम बन सकती है। इंटरनेट के क्षेत्र में भी हालात अलग नहीं हैं। सोशल मीडिया, सर्च इंजन और डेटा स्टोरेज जैसे प्लेटफॉर्म विदेशी स्वामित्व में हैं, जिससे डेटा सुरक्षा और डिजिटल संप्रभुता पर सवाल उठते हैं। यह केवल आर्थिक नहीं, बल्कि रणनीतिक चुनौती भी है।

इसके साथ ही, भारत में मौलिक आविष्कारों की कमी भी चिंता का विषय है। आईटी सेवाओं में मजबूती के बावजूद, शोध और पेटेंट के मामले में भारत अभी पीछे है। रिसर्च और डवलपमेंट पर कम निवेश इसकी वजह हैं। ऐसे में आत्मनिर्भरता के लिए तकनीकी नवाचार को प्राथमिकता देना अनिवार्य हो गया है। यह परिदृश्य हमें बाध्य कर रहा है कि हम आत्मनिर्भरता के उस विचार की ओर लौटें, जिसे हम अक्सर नारे के रूप में इस्तेमाल करते आए हैं, लेकिन उसे व्यवहार में पूरी तरह उतार नहीं पाए हैं। आत्मनिर्भरता का अर्थ दुनिया से कट जाना नहीं है, बल्कि इतना सक्षम बनना है कि वैश्विक उथल–पुथल का असर सीमित किया जा सके। मौजूदा समय में सवाल यह नहीं है कि भारत को वैश्विक व्यापार से दूरी बनानी चाहिए या नहीं, बल्कि यह है कि क्या हमारी अपनी नींव इतनी मजबूत है कि बाहरी झटकों को सह सके?

समय की मांग है कि हमें ऊर्जा के क्षेत्र में वैकल्पिक रास्तों की ओर तेजी से बढ़ना चाहिए। सौर और पवन ऊर्जा अब केवल पर्यावरण का मुद्दा नहीं रहे हैं, बल्कि आर्थिक स्थिरता का आधार भी बन चुके हैं। इसी प्रकार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत करना, छोटे उद्योगों को तकनीक और वित्तीय सहायता देना और कृषि उत्पादों की प्रोसेसिंग को बढ़ावा देना जरूरी है, क्योंकि ऐसे कदम ही भारत को भीतर से सशक्त बना सकते हैं।

इस बीच, कुछ ऐसे सवाल भी हैं जिनका उत्तर हमें खोजना चाहिए। बड़ा सवाल है कि क्या हमने सस्ते आयात के लालच में अपनी उत्पादन क्षमता को कमजोर कर दिया है? क्या हमारी नीतियां दीर्घकालिक सोच के बजाय तात्कालिक लाभ पर अधिक केंद्रित रही हैं? और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या हम हर संकट के बाद कुछ समय के लिए जागते हैं और फिर वही पुरानी लापरवाही ओढ़ लेते हैं? दुनिया में अस्थिरता निरंतर बढ़ रही है। कभी इस देश में तो कभी उस देश में कुछ न कुछ संकट खड़ा हो ही जाता है।

मानना पड़ेगा कि दुनिया में अस्थिरता अब अपवाद नहीं रही है बल्कि एक स्थाई स्थिति बनती जा रही है। एक युद्ध खत्म होता नहीं है तो दूसरा शुरू हो जाता है। ऐसे में यह उम्मीद करना कि सब कुछ सामान्य रहेगा, शायद खुद को धोखा देने जैसा ही होगा। हमारे सामने चुनौती यह नहीं है कि वह इन युद्धों को रोक सके बल्कि बड़ी चुनौती यह है कि हम इनके प्रभाव को अपने यहां किस हद तक सीमित कर पाते हैं। जब दुनिया जलती है तो उसकी आंच से बचना संभव नहीं है लेकिन हम अपने घर को आग से बचाने के प्रयत्न तो कर ही सकते हैं। आत्म निर्भरता उसी बचाव का नाम है। आत्म निर्भरता ही एक ऐसा कवच है, जो हमें संकट से बचा सकता है। हमारा देश आत्मनिर्भर बने, इसके लिए कदम उठाने ही होंगे। इसके लिए सरकार, हमारे नीति नियंताओं, नागरिकों, संस्थाओं को मिलकर काम करना होगा। यह परिहार्य है, इस बात को समझा जाना चाहिए।

प्रो. महेश चंद गुप्ता
लेखक प्रख्यात विचारक,
चिंतक और वक्ता है)

राशिफल बुधवार 8 अप्रैल, 2026

पंडित अनिल शर्मा

वैशाख मास शुक्ल पक्ष, षष्ठी तिथि, बुधवार, विक्रम सम्वत 2083, मूल नक्षत्र गुरुवार प्रात: 8.48 तक, वारियान योग सायं 5.10 तक वाणिज करण सायं 7.02 तक, चन्द्रमा आज धनु राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति – सूर्य–मीन, चन्द्रमा–धनु, मंगल–मीन, बुध–कुम्भ, गुरु–मिथुन,शुक्र–मेष, शनि–मीन, राहु–कुम्भ, केतु–सिंह राशि में संचार करेगा। आज यमघट योग सूर्योदय दिन रात होगा। कुमार योग सायं 7.02 तक है। रवियोग सम्पूर्ण दिनरात रहेगा। भद्रा सांय 7.02 से आरम्भ होगा।

श्रेष्ठ चौघडिया – लाभ–अमृत सूर्योदय से 9.22 तक शुभ 10.55 से 12.29 तक, चट 3.36 से 5.10 तक

राहुकाल – 12.00 से 1.30 तक सूर्योदय 6.14 सूर्यास्त 6.43

मेष

अपनी कार्य योजना को सीमित रखें। पारिवारिक कारणों से मानसिक तनाव रहेगा। आज आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। बनते कार्य बिगड़ सकते हैं।

वृष

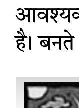

व्यावसायिक/आर्थिक मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। अटका धन प्राप्त होगा। चलते कार्यों में प्रगति होगी। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी। परिवार में आपसी सहयोग–समन्वय बना रहेगा।

मिथुन

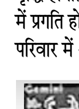

अस्त–व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। विवादित मामलों का निपटारा हो सकता है। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

कर्क

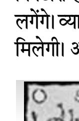

परिजनों के व्यवहार के कारण दु:ख हो सकता है। आज आवश्यक कार्यों के संबंध में दुविधा बनी रहेगी। खान–पान के कारण स्वास्थ्य खराब हो सकता है।

सिंह

घर–गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। परिवार में आपसी मतभेद बढ़ सकते हैं, स्वास्थ्य संबंधित परेशानी हो सकती है। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे।

कन्या

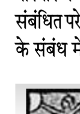

परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। आज मित्रों/रिश्तेदारों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

तुला

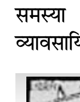

व्यावसायिक कार्यों से संबंधित आर्थिक समस्या का समाधान हो सकता है। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। नवीन कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। घर–परिवार में धार्मिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

वृश्चिक

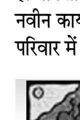

व्यावसायिक कार्यों के संबंध में उचित सोच–विचार हो सकता है। महत्वपूर्ण मामलों में उचित परामर्श मिल सकता है। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

धनु

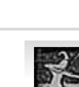

पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। मन में असंतोष बना रहेगा। घर–गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। परिवार में आपसी वाद–विवाद हो सकते हैं।

मकर

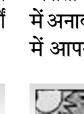

आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। संभावित स्त्रोत से धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी। घर–परिवार में सुख–शांति बनी रहेगी।

कुंभ

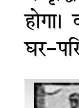

व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। चलते कार्यों में प्रगति होगी। नवीन कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मीन

नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। धार्मिक कार्यों में भाग ले सकते हैं।